अमृत वाणी

जिस तरह घोंसला सोती हुई चिड़िया को आश्रय देता है उसी तरह मौन तुम्हारी वाणी को आश्रय देता है।

– रवींद्रनाथ ठाकुर

बंद होना चाहिए अवैध वसूली का यह धंधा

घर में बच्चे के जन्म के नाम पर पहले तालियां पीटकर बधाई के गीत गाना और फिर मांग अनुसार रकम नही मिलने पर शोर शराबा और बद्दुआ देने पर उतर आना एक वर्ग के कुछ लोगों का धंधा बन गया है। कभी दो चार तो कभी बकायदे एक दल के आकार में पहुंच जाते है वे उन घरों में, जिनके बारे में पूरी खबर ये लोग पहले ही जुटा लेते है कि इनके घर में हाल ही में बेटा बेटी या पोता पोती का जन्म हुआ है और साथ ही वे कितने बड़े लोग हैं ताकि उनसे कमाई का एक अनुमान लगाया जा सके। उसी अनुसार ये लोग अपना यथासंभव दवाब भी बनाते है और जब दाल गलती नजर नहीं आती तो अपने ब्रम्हास्त्र बद्दुआ का उपयोग करते हैं।

दरअसल लोगों की यह एक आम धारणा है कि इस वर्ग की महिलाओं की दुआ और बद्दुआ दोनों ही बहुत प्रभावी होती है। इसलिए लोग खासकर इनकी बद्दुआ से बहुत डरते है। जाहिर तौर पर ये लोग भी लोगों की इस कमजोरी का हरसंभव लाभ उठाने की कोशिश करते हैं।

रायपुर के उस व्यापारी के मसले पर नजर डालें जिसमें पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। इस व्यापारी के घर पोते के जन्म पर पहले तो ये लोग बधाई का सुर अलापने लगे फिर एक दम से 15 हजार रुपये की मांग कर डाली। व्यापारी दो हजार रुपये तक देना चाहा पर वे नही माने और अपने स्वभाव के अनुकूल बद्दुआ की धमकी पर उतर आए जो सहज ही लोगों को व्याकुल कर देता है। इस व्यापारी ने मजबूर होकर जब पुलिस बुलाई तब जाकर उन्हें राहत मिली वहीं इन लोगों के भी कई हरकतों से पर्दा उठा। वस्तुतः बड़े घरों में बच्चों के जन्म का लभ उठाने का अवसर उन्हें सीमित ही मिलती है इसलिए इन्होंने अपने इस अवैध वसूली के धंधे को जीवित रखने और भी कई रास्ते ढूंढ लिए है। हर छोटे बड़े त्योहार के नाम पर भी ये लोग घर घर घूमकर अपना व्यवसाय चलाते हैं। पुलिस ने इनके व्दारा रेकी करने का जो खुलासा किया। है वो भी गलत नही है क्योंकि बताया जाता है कि इन वसूली कर्ताओं के दल में वेश बदलकर कुछ ऐसे लोग भी शामिल होते है जो इनके वर्ग के नही है। मेहनत से जी चुराकर आसान कमाई के लिए वे इनके साथ हो लेते हैं और मौका देखकर रेकी तो क्या इनके व्दारा किसी भी तरह के गलत कार्य में संलग्न होने से इन्कार नही किया जा सकता।

कुछ समय पूर्व ऐसे ही लोगों व्दारा ट्रेन में भी यात्रियों को परेशान कर उनसे अवैध वसूली करने की शिकायतें आ रही थी जिस पर मुश्किल से कुछ हद तक नियंत्रण किया गया है।

इसलिए जरुरी है कि इस अवैध धंधे पर कड़ाई से रोक लगे। इसके लिए आम लोगों को भी अपनी कमजोरियों से ऊपर उठकर जहां पुलिस का साथ देना होगा वही पुलिस को भी अपनी सक्रियता दिखानी होगी।

राजकाज

भाजपा की नकली खुशी

उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत का जश्न मनाने वालों को शायद यह नहीं मालूम कि अंदरुनी तौर पर भाजपा की बुरी तरह हार हुई है। दरअसल आंकड़े बता रहे हैं कि भाजपा के उम्मीदवारों की बड़ी संख्या में जमानत जब्त हुई है। इसलिए कहा जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव में भाजपा भले ही यूपी से लेकर गुजरात तक जश्न मना रही होए लेकिन हकीकत में देखा जाए तो प्रदेश के 652 नगर निकायों में से 243 नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के अध्यक्ष पदों पर भाजपा के प्रत्याशी जमानत भी नहीं बचा सके हैं। यही नहीं बल्कि नगर निगम में पार्षद नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में सदस्य के पदों पर भी भाजपा के 46 फीसदी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है। इस प्रकार गुजरात चुनाव के मद्देनजर भाजपा नकली खुशी का इजहार करने में लगी हुई हैए हकीकत तो वह दर्द से कराह रही है।

लालू के कारण परिजन परेशान

लालू यादव की वजह से उनके परिवार वालों को भी अच्छी.खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते जहां बिहार में नीतिश कुमार गठबंधन तोड़कर भाजपा के साथ हो लिए वहीं लालू की बेटी मीसा भारती और दामाद पर ईडी का शिकंजा कसता चला जा रहा है। गौरतलब है कि चारा घोटाले के बाद लालू राजनीतिक तौर पर हाशिये पर चले गए और उनकी जगह राबड़ी देवी मुख्यमंत्री पद पर रहीं लेकिन अब जबकि वो सत्ता में ही नहीं हैं तो उन पर तरह.तरह से शिकंजा कसने की राजनीति जारी है। ऐसे में जानकार कह रहे हैं कि यदि लालू ने राजनीतिक क्षेत्र से संयास नहीं लिया और उन पर सख्त कार्रवाई होने के साथ परिजनों को यूंही परेशान किया जाता रहा तो इसे राजनीतिक विद्वेष के तहत की गई कार्रवाई ही कहा जाएगा।

संघीय गणतंत्र के रास्ते पर नेपाल

लंबी राजनीतिक जद्दोजहद के बाद आखिरकार नेपाल ने नये संविधान के प्रावधानों के मुताबिक, संघीय गणतंत्र की राह पर पहला कदम रख दिया. पिछले तेईस नवम्बर को देश की संसद और प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव के लिए पैंसठ फीसद मतदाताओं ने अपना वोट दिया. अंतिम चरण का मतदान सात दिसम्बर को होगा. देश की खंडित बहुदलीय राजनीति में मुकाबला दो गठबंधनों के बीच है.

एक ओर देश की दो प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टियां-नेकपा (यूएमएल) और नेकपा (माओवादी) का 'वामपंथी अलायंस' है, तो दूसरी ओर नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाला 'डेमोक्रेटिक अलायंस' है. इस गठबंधन में नेपाल शक्ति पार्टी, पहले की राजा और पंचायत समर्थक पार्टियां और मधेशियों के छोटे-छोटे दल हैं. ये दोनों गठबंधन चुनाव पूर्व हुए हैं, इसलिए इन्हें अनैतिक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अनेक सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों को लेकर इनके बीच गहरा अंतरविरोध है.

इसलिए चुनाव बाद बनने वाली सरकार राजनीतिक स्थिरता दे पाएगी, इस बारे में आस्त नहीं हुआ जा सकता. नेपाली कांग्रेस का झुकाव मध्य से दक्षिण की ओर है, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर इनकी सामाजिक-आर्थिक नीतियों में कोई वैचारिक अंतर दिखाई नहीं देता. विदेश नीति के मामले में फर्क जरूर है. नेपाली कांग्रेस को भारत समर्थक और कम्युनिस्ट पार्टियों को चीन समर्थक माना जाता है.

नये संविधान के निर्माण के दौरान राजनीतिक विमर्श में दो मुद्दे सबसे ज्यादा उभर कर सामने आए थे. शक्तियों का विकेंद्रीकरण और शासन-सत्ता में समाज के हाशिये पर रहने वाले तबकों को उचित प्रतिनिधित्व दिलाया. लेकिन नये संविधान में मधेशियों और जनजातियों की राजनीतिक आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाई हैं.

माओवादी नेता प्रचंड इनकी मांगों के प्रति नरम रुख रखते हैं, और संविधान में संशोधन के इच्छुक भी, जबकि नेकपा (यूएमएल) के नेता केपी ओली इसके प्रबल विरोधी हैं. अब ये दोनों कम्युनिस्ट पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं. इसी तरह, राज्यों के पुनर्गठन और अन्य मुद्दों पर नेपाली कांग्रेस और नया शक्ति पार्टी के बीच मतभेद है. यानी जन सरोकारों के अहम मुद्दों पर अनिश्चितता कायम है.

नेपाल के हर चुनाव में भारत विरोध का मुद्दा हॉट-केक की तरह बिकता है. इस चुनाव में भी नेकपा (यूएमएल) के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली नाकेबंदी का मुद्दा जोर-शोर से उछाल रहे हैं. उन्होंने पिछले दिनों मधेशी आंदोलन और नाकेबंदी के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया था. वे चुनाव सभाओं में लोगों को आस्त करते हैं कि प्रधानमंत्री रहते हुए हमने चीन के साथ पारगमन संधि की है, जिसके कारण भारत की नाकेबंदी का नेपाल पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

उनका यह रुख भारत की परेशानी का कारण बन सकता है. स्थानीय निकायों के चुनाव में नेकपा (यूएमएल) का प्रदर्शन अच्छा रहा है. इसलिए वामपंथी अलायंस के जीतने की संभावनाएं ज्यादा हैं. सवाल है कि सत्ता के लिए छोटी-छोटी बातों पर लड़ने वाले दलों का गठबंधन चुनाव बाद क्या एक रह पाएगा? नेताओं को यह काम करना चाहिए क्योंकि भारी संख्या में मतदान में हिस्सा लेकर जनता अपना कर्तव्य निभा रही है. अब नेताओं की बारी है.

– डॉ. दिलीप चौबे

(ये लेखक के अपने विचार है)

पाकिस्तान पर कट्टरपंथी ताकतें हावी

माईनेशन इट्स टाइम टु मेक अ चेंज' यह संदेश पाकिस्तान के उस तंजीमी संगठन का है, जिसने इस्लामाबाद को 27 नवम्बर को सजदा और पायबोस करा दिया.

न केवल इस्लामाबाद की सरकार के कानून मंत्री को इस्तीफा देने पर विवश कर दिया बल्कि दुनिया को भी इस्लामाबाद की निर्वाचित सरकार की हैसियत बता दी. इस संगठन का नाम है तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (या रसूल अल्लाह). इसका मुखिया चंद दिनों में एक मस्जिद के खादिम की हैसियत से ऊपर उठकर पाकिस्तान के बरेलवी संप्रदाय का ऐसा नेता बन गया है, जिसके पीछे कुछ राजनीतिक दल एवं सेना खड़ी है. क्या लब्बैक द्वारा इस्लामाबाद की घेराबंदी की सफलता को देखकर नहीं लगता कि पाकिस्तान की कट्टरपंथी जमातें रियल स्टेट एक्टर नहीं हैं, तो उसके बराबर की हैसियत वाली जरूर हैं?

आखिर, लगभग ढाई साल की उम्र और लगभग 3000 सदस्यों वाला एक कट्टरपंथी संगठन सेना और सरकार को पेट के बल लेटने को मजबूर करने में कैसे सफल हो गया? आखिर, क्यों जनरल बाजवा इसके खिलाफ कार्रवाई के बजाय सरकार को सुझाव देते हुए नजर क्यों आए कि 'मार से नहीं, प्यार से बात की जाए'? बाजवा के इस प्यार को तो पाकिस्तान की न्यायपालिका भी हजम नहीं कर पाई. पूछने पर मजबूर हो गई कि आपका रद्द उल फसाद कहां है? क्या सेना को इस प्रदर्शन में कोई फसाद नजर नहीं आता? सवाल यह भी उठता है कि आखिर, पाकिस्तान में अदना सा मौलवी देखते ही देखते पूरे देश को एक कैदखाने में तब्दील करने की ताकत कहां ले आता है?

5 नवम्बर से धरना शुरू करने वाले तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने 27 नवम्बर को दिखा दिया कि पाकिस्तान में असली ताकत जम्हूरियत में नहीं जिहाद में निहित है. बात इतनी सी थी कि 2 अक्टूबर को पाकिस्तान की संसद ने चुनाव सुधार विधेयक, 2017 पारित किया था, जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों के शपथ से 'खात्मे नबूव्वत या पैगम्बर मोहम्मद' वाले खंड को हटा दिया गया था. इसके दो दिन बाद तंजीमी जमातों ने सरकार को इस खंड को वापस जोड़ने के लिए मजबूर कर दिया. नेशनल असेंबली में इसे क्लैरिकल गलती बताकर सुधार भी लिया गया. लेकिन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) ने कानून मंत्री जाहिद हमीद को चुनावी शपथ में बदलाव का दोषी माना. इसे ईशनिंदा के समान मानते हुए सजा का हकदार करार दिया. हालांकि हमीद ने माफी मांग ली थी, लेकिन टीएलपी ने उनके इस्तीफे की मांग को लेकर 5 नवम्बर को एक अन्य धार्मिक पार्टी सुन्नी तहरीक के साथ मिलकर फैजाबाद इंटरचेंज पर धरना शुरू कर दिया जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच यातायात का मुख्य मार्ग है. सरकार की तरफ से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई विफल रही तो उसने सेना से मदद मांगी. सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी को मशविरा दिया कि प्रदर्शनकारियों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से निपटा जाए. यह भी कहा कि वह 'अपने ही लोगों पर ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकती.' परिणामतः सरकार ने जिहादियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. लेकिन जीता कौन-सेना या जिहादी?

कट्टरपंथियों के आगे इस तरह से सरकार का समर्पण सीधे तौर पर साबित करता है कि यह सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की हार है. लेकिन सच तो यह है कि यह पाकिस्तान के लोकतंत्र या पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट की हार है. जिस देश में कट्टरपंथी संगठन इतनी ताकत हासिल कर ले जाएं कि तय करने लगें कि क्या इस्लामी है, क्या नहीं, कौन काफिर है, कौन ईमान वाला, किसने ईशनिंदा की है, कौन गुनहगार है, कौन पश्चिमी देशों का एजेंट है, कौन पाकिस्तानपरस्त? तो मान लेना चाहिए कि उस हैसियत को प्राप्त कर चुके हैं कि वे ही राष्ट्र हैं. दरअसल, इस पूरे प्रकरण के पीछे सेना की अहम भूमिका थी.

गौर से देखें तो पाकिस्तान की सेना नवाज शरीफ से उसी समय से खफा थी, जब भारतीय सेना द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी. सेना ने उसी समय से इस्लामाबाद को कमजोर करना शुरू कर दिया था. रावलपिंडी से सेना प्रवक्ता पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था और कूटनीतिक विषयों पर बयान देने लगे थे. लेकिन इसके बाद भी नवाज को हटाने के लिए पाकिस्तान में कोई आंदोलन नहीं चला. इसलिए कि उनके पास कम से कम पंजाब प्रांत के दक्षिणपंथी मजहबी मतदाताओं को आकर्षित रखने का हुनर तो है ही. लेकिन सितम्बर में चुनाव में तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान या रसूल-उल-उल्लाह' उसमें सेंध लगाता दिखा यानि लब्बैक वही कर रहा है, जो सेना चाह रही थी. आकलन करने से पता चलता है कि इस्लामाबाद की सरकार मौलवी के लब्बैक के पीछे की ताकत को पहचान नहीं पाई लेकिन उसने टीवी चैनलों पर खबरों का ब्लैकआउट और सोशल मीडिया व न्यूज वेबसाइट्स को पूरी तरह जनता की पहुंच से दूर करने की कोशिश की. जिस देश की अर्थव्यवस्था लगभग फेल होने की कगार पर हो, आर्थिक दिक्कतें लोगों को परेशान कर रही हों, बेरोजगारी चरम पर हो, युवा दिशाहीन हो रहा हो और कानून-व्यवस्था चौपट है।

– रहीस सिंह

(ये लेखक के अपने विचार है)

विकास दर : ऊंचाई की तरफ

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्तीय वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही जुलाई-सितम्बर में आर्थिक वृद्धि के जो आंकड़े पेश किए हैं, उनमें सकारात्मक और उत्साहवर्धक बदलाव दिखाई दे रहा है. सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में 6.3 फीसद की दर से बढ़ोतरी हुई है. पिछली तिमाही में यानी अप्रैल से जून के दरान जीडीपी वृद्धि दर 5.7 फीसद थी. लगातार कई तिमाहियां में जीडीपी की गिरावट के बाद सुधार यह बताता है कि अर्थव्यवस्था ने नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) जैसे अल्पकालिक आर्थिक झटकों को पीछे छोड़ दिया है. स्थिति यह है कि पिछले एक वर्ष से चले आ रहे अल्पकालीन आर्थिक प्रभाव कम हो गए हैं और आर्थिक सुधारों की प्रगति दिखाई दे रही है.

यदि हम नए आंकड़ों का विश्लेषण करें तो पाते हैं कि इस दूसरी तिमाही में जीडीपी को जो गति मिली है, उसके लिए विनिर्माण क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है. दूसरी तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि 7 फीसद रही थी. जबकि पिछली तिमाही में यह महज 1.2 फीसद थी. लेकिन कृषि क्षेत्र में विकास दर घटी है और यह 1.7 फीसद रही जबकि पहली तिमाही में यह 2.3 फीसद थी. जिन क्षेत्रों में 6 फीसद से ज्यादा वृद्धि दर्ज हुई, उनमें विनिर्माण के अलावा बिजली, गैस, जल आपूर्ति, होटल, परिवहन एवं संचार तथा प्रसारण से जुड़ी सेवाएं शामिल हैं. स्पष्ट है कि उत्पादन और उपभोग दोनों ही मामलों में अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी है. नोटबंदी और जीएसटी के प्रभाव बीते हुए दिखाई दे रहे हैं. ऐसे में आने वाली तिमाहियों में वृद्धि की रफ्तार और भी तेज होने की उम्मीद है. स्पष्ट है कि पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही से अर्थव्यवस्था में जो सुस्ती आई थी, उसका पहिया अब पलटता हुआ दिखाई दे रहा है. वर्ष 2017 की शुरुआत में अर्थव्यवस्था के बदलाव की जो चुनौतियां झेलनी पड़ी थीं, वह दौर गुजरते हुए दिखाई दे रहा है और आगे लगातार बेहतरी के आसार दिख रहे हैं.

निस्संदेह अब वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही के आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि आर्थिक बदलाव के दौर में अर्थव्यवस्था निवेश और कारोबार सुधार की ओर बढ़ी है. पिछले कुछ दिनों में देश की क्रेडिट रेटिंग बढ़ने और कारोबार आसान बनाने से संबंधित जो नई महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित हुई हैं, वे स्पष्ट संकेत दे रही हैं कि वर्ष 2017 में निवेश व कारोबार के मामले में भारत का परिदृश्य बदला है. पिछले दिनों 17 नवम्बर को अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को बीएए-3 से बढ़ाकर बीएए-2 कर दिया है.

वर्ष 2004 के बाद यानी 13 साल बाद मूडीज ने भारत की रेटिंग में सुधार किया है. रेटिंग में सुधार के लिए मूडीज ने ये कारण प्रस्तुत किए हैं-भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में हो रही बढ़ोतरी, नोटबंदी और जीएसटी के लाभ, डूबते कर्ज से पैदा हुई बैंकिंग की समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा दिया गया पैकेज, देश भर में तेजी से बढ़े आधार कार्ड और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के लाभ. मूडीज ने यह भी कहा है कि वर्ष 2017-18 में भारत की विकास दर 7.5 फीसद होगी. इसी तरह, बीती 31 अक्टूबर 2017 को विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रैंकिंग में 190 देशों की सूची में भारत 100वें नंबर पर पहुंच गया है. इतना ही नहीं, विश्व बैंक ने भारत को इस साल सबसे ज्यादा सुधार करने वाले दुनिया के शीर्ष 10 देशों की सूची में शामिल किया है.

निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव के लिए विकास के साथ-साथ रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जाना होगा. विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर बढ़ानी होगी. कर अनुपालन और भुगतान को और सरल किया जाना होगा. जीएसटी का क्रियान्वयन सरल बनाया जाना होगा. सरकारी बैंक के पुनपरूजीकरण को कारगर तरीके से नियंत्रित करना होगा. कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने और कंस्ट्रक्शन परमिट में अब भी काफी वक्त लगता है, उसे कम किया जाना होगा. बैंकिंग व आर्थिक मामलों में कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया को तेज करनी होगी. प्रॉपर्टी खरीदना और इसका रजिस्ट्रेशन कराना भी आसान बनाने की जरूरत है. उद्यमियों के लिए नौकरशाही कम करने, पैसे का लेन-देन आसान करने की जरूरत है. रोजगार, निर्यात और निजी निवेश बढ़ाने के कारगर प्रयास किए जाने होंगे. कारोबार के विभिन्न कदमों को तेज करने के लिए भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना होगा.

– जयंतीलाल भंडारी

(ये लेखक के अपने विचार है)

पकड़े प्रदूषण को कान

दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में चल रहे भारत-श्रीलंका टेस्ट मैच के दूसरे दिन श्रीलंकाई खिलाड़ी मास्क पहनकर मैदान में उतरे। 122वें ओवर की तीसरी बॉल फेंकने के बाद तेज गेंदबाज लाहिरू गमागे मैदान पर ही उल्टी करने लगे। हवा इतनी गंदी हो चली थी कि श्रीलंकाई खिलाड़ी फील्ड से बाहर जाना चाहते थे, लेकिन अंपायर्स ने समझा-बुझाकर रुका मैच चालू कराया। इसके बाद गमागे दोबारा बॉलिंग करने आए तो ओवर पूरा करते ही उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा।

इसी तरह सुरंगा लकमल भी 124वें ओवर की पांचवीं गेंद फेंकने के बाद वापस चले गए और उनका ओवर दिलरुवान परेरा ने पूरा किया। हालात कुछ यूं बने कि एक वक्त श्रीलंका के दस खिलाड़ी ही मैदान पर थे और ग्यारहवें की जगह आने के लिए श्रीलंका का कोई रिजर्व खिलाड़ी तैयार नहीं था। जब श्रीलंकाई खिलाड़ी खांस-खांसकर बेदम हुए जा रहे थे तो कोटला मैदान में मौजूद बीस हजार दर्शक उन्हें लूजर्स-लूजर्स कहकर चिढ़ा रहे थे। ठीक उसी वक्त फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट डायरेक्टर जेवियर सेपी ने ट्वीट किया कि दिवाली से लेकर फरवरी तक दिल्ली में खेल इवेंट नहीं होने चाहिए। बावजूद इसके, कमेंट्री बॉक्स में लक्ष्मण, नेहरा और आकाश चोपड़ा आदि ने श्रीलंकाई टीम पर व्यंग्य किया कि दिल्ली में खेलना है तो फेफड़े मजबूत करके आना होगा। बीसीसीआई के अध्यक्ष तक कहने लगे कि औरों को नहीं तो इन्हें ही इतनी प्रॉब्लम क्यों है?

अगले दिन ब्रिटेन के अखबार संडे एक्सप्रेस ने बड़ी स्टोरी के साथ बताया कि दिल्ली में क्रिकेट के इतिहास का यह काला पन्ना कैसे जुड़ा। तब जाकर एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि इस हाल में मैच ही नहीं कराना था। यह भी सामने आया कि जिस वक्त श्रीलंकाई खिलाड़ी परेशान हुए, उस वक्त हवा वाकई जहरीली हो चुकी थी। 2008 ओलिंपिक के पहले चीन में जब स्मॉग के चर्चे उठे तो वहां सरकार ने प्रदूषण के सभी कारकों को कान पकड़कर पेइचिंग से इतनी दूर बिठाया कि आज तक उन्हें बेकाबू नहीं होने दिया। मगर अपने यहां कान तो दूर, हवा में जहर भरनेवालों की उंगली तक पकड़ने की न तो हिम्मत दिखती है, न इच्छाशक्ति। शिकायत करनेवालों को लूजर कहकर चिढ़ानेवाले गौर से सोचें कि छवि से लेकर स्वास्थ्य तक असली लूजर कौन है।